IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (SHRI EDUARDO FALEIRO) : (a) to (d) The prices of leader packs of formulations based on bulk drugs Ranitidine were notified on 20-6-1988 on the basis of weighted average import price of Rs. 4396/- kg. computed for 9 months period of 1987-88. After the promulgation of the Drug (Prices Control) Order, 1987, the then major producer of Ranitidine was exempt from price control under the provisions of DPCO, 1987 for 5 years. On the expiry of this period cost-cum-technical study of this has been taken up by BICP.

GOVERNMENTS PROCRASTINATION IN FINALISING NEW DRUG POLOCY.

3037. SHRI KAMAL MORARKA : Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 884 given in the Rajya Sabha on the 9th December, 1993 and state :

(a) what are the reasons for not finalising the New Drug Policy;

(b) whether Government have sought proposals from pharmaceutical industry on pricing and monitoring mechanism,

(c) whether any proposals have been received; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (SHRI EDUARDO FALEIRO) : (a) to (d) Consultation with various interest groups, including the Pharmaceutical Industry, formed part of the review of Drug Policy, 1986. Discussions on this subject have taken place in the House on 18th, 19th and 23rd August, 1993. Consideration of the matter is now in an advanced stage.

एच.एफ.सी. द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं

3038. श्री राम सिंह राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1985-90 की अवधि के दौरान एच.एफ.सी. द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं में काफी विलम्ब हुआ है और उनकी लागत में भी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एडुआर्डो फलेरिओ) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) द्वारा 1985-90 की अवधि के दौरान हाथ लेकी गयी परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबन्ध में दिए गए हैं। (देखिये) [परिशिष्ट 169, अनुषंग सं. 60] इससे पता चलता है कि हल्दिया परियोजना को छोड़कर अन्य मामलों में अनुमोदित संशोधित लागत अनुमानों में कोई लागत वृद्धि नहीं हुई।

(ग) और (घ) विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमाएं निर्धारित की गयी थी।